बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

(भाग १--कार्यवाही--प्रश्नोत्तर ।)

मंगलवार, तिथि ६ सितम्बर, १९६६ ।

विषय-सूची ।

	पृष्ठ ।
प्रश्नों के लिखित उत्तर --	
प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा की मेज पर रखा जाना	१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर --	
तारांकित प्रश्न संख्या ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ एवं १२--५५ ..	१--५६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३	५६-५७
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर)	५८--८९
दैनिक निबन्ध	९१-९३

टिप्पणी--जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे ऐसा (*) चिह्न लगा दिया गया है

हिन्दुस्तान व्हेकिल्स, लिमिटेड, फुलवारीशरीफ में उत्पादन।

१०४८। श्री यदुनन्दन झा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि "हिन्दुस्तान व्हेकिल्स, लि०, फुलवारीशरीफ, पटना" को सरकार ने २७ सितम्बर १९६५ से अपने नियंत्रण में लिया है ;

(२) यदि खंड (१) का उत्तर 'हां' में है तो, उक्त तिथि से जनवरी, १९६६ तक कितनी बाइसिकलें तथा बाइसिकलों के कितने पार्ट-पूर्जे बने ; यदि नहीं तो क्यों ;

(३) क्या हिन्दुस्तान व्हेकिल्स, लि०, फुलवारीशरीफ, पटना में वांछित उत्पादन नहीं हो रहा है ; यदि हां, तो सरकार इसके विषय में क्या कदम उठा रही है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) बड़ी ही अव्यवस्थित स्थिति में यह कम्पनी ली गई। कम्पनी के सभी कागजातों की जांच करने के पश्चात् यह देखा गया कि कम्पनी पर लगभग एक करोड़ रुपये का दायित्व है, जिसमें युनाइटेड बैंक आफ इंडिया का १९ लाख रुपये का कर्ज है। इस कर्ज में कम्पनी का सभी कच्चा माल, डाइज, टूल्स जिग्स इत्यादि बन्धक (hypothecated) है। उत्पादन के लिये इन सामग्रियों को छुड़ाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त इस कम्पनी पर लगभग एक करोड़ का दायित्व है, जबकि इसकी सम्पत्ति लगभग ४० लाख से अधिक की नहीं है। इस कम्पनी को चलाने में एक बड़ी रकम की आवश्यकता होगी, जिसे बिहार सरकार के लिये वहन करना आसान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सारी परिस्थिति से अवगत कराया है एवं उनके उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

उपर्युक्त स्थिति में उत्पादन का काम बन्द-सा है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। बिहार सरकार के अनुरोध पर यह सारा विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

वकस यूनियन, हसनपुर को मान्यता।

१०४९। श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि गत १९६५ के अप्रील महीने में न्यू इंडिया शूगर फैक्ट्री के दो प्रतिद्वन्दी यूनियन मजदूर सेवक संघ संबंधित आई० एन० टी० यू०सी० और वकस संबंधित हिन्द मजदूर सभा के बीच प्रतिनिधित्व के दावे को लेकर मजदूरों से मौखिक मतदान लिया गया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त अवसर पर वकस यूनियन ने यह निरोध-पत्र दिया था कि आई० एन० टी० यू० सी० से संबंधित मजदूर सेवक संघ के द्वारा जो सदस्यों की सूची दी गयी है उसने सदस्य-शुल्क तीन रुपये के बदले एक रुपया ही दिया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि हिन्द मजदूर सभा से संबंधित वकस यूनियन को ६७ फीसदी मत लिया जो साधारण बहुमत से बहुत ज्यादे है ;

(४) क्या यह बात सही है कि गत अगस्त के त्रिदलीय सम्मेलन में (जो दिल्ली में हुआ था, जिसमें बिहार सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे) यह निर्णय हुआ कि साधारण बहुमत के आधार पर ही यूनियन को मान्यता प्रदान की जाय ;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार वर्कर्स यूनियन, हसनपुर को अब तक मान्यता क्यों नहीं दे रही है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) हिन्द मजदूर सभा से संबंधित न्यू इन्डिया सूगर मिल्स वर्कर्स यूनियन को ६६.६४ प्रतिशत कर्मचारियों का मत प्राप्त हुआ ।

(४) २१ अगस्त १९६५ को दिल्ली में हुई उद्योग अनुशासन संहिता के कार्य संबंधी हुई गोष्ठी में परामर्श दिया है कि मान्यता के लिए साधारण बहुमत का सिद्धान्त मानना चाहिये । परन्तु मान्यता के संबंध में राज्य सरकार अपनी प्रक्रिया को मानने के लिये बाध्य है, जो कि बिहार केन्द्रीय श्रम परामर्शदात्र के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा स्वीकृत है ।

(५) चूंकि न्यू इंडिया सूगर मिल्स वर्कर्स यूनियन को सदस्य कामगारों का ७५ प्रतिशत से कम मत प्राप्त हुआ है, यह यूनियन मान्यता का अधिकारी नहीं है ।

प्रधान सहायकों के वेतन निर्धारण में गड़बड़ी ।

१०५०. श्री मोती राम—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि वेतन निर्धारण समिति ने अपने प्रतिवेदन की कंडिका १०७ में उच्चवर्गीय सहायकों के वर्ग (१) और (२) के कार्य एवं उत्तरदायित्व को समान मानकर एक ही वेतनक्रम की सिफारिश की है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त सिफारिश को आधार मानकर सरकार के वित्त विभाग ने दोनों वर्गों को मिलाकर प्रधान सहायकों का एक ही वेतन क्रम ३५५—५८० रु० १ ली अप्रील से लागू किया है ;

(३) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या ६७-एफ०, दिनांक १० मार्च १९६६ के अनुसार उच्चवर्गीय सहायकों के द्वितीय वर्ग के सहायकों को जिन्होंने उच्चवर्गीय सहायक वर्ग (१) के पद पर दो-चार दिन से कुछ महीनों तक की अवधि के लिये स्थानापन्न किया है नए वेतनक्रम लागू करने की तिथि के चुनाव की छूट प्रदान की गई है ;

(४) यदि खंड (३) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या यह बात सही है कि उक्त व्यवस्था के लागू होने के समान उत्तरदायित्व वाले एवं समकक्ष कर्मचारियों के बीच एक ही प्रकार के काम करते रहने पर भी वेतन की असमानता में वृद्धि हो जाती है ;

(५) यदि खंड (१), (२) और (४) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वेतन निर्धारण के फलस्वरूप प्रधान सहायकों के वेतन में असमानता तथा गड़बड़ी को दूर करने के लिये सरकार कौन-सी कार्रवाई कर रही है ?